कागजात भी नहीं बनाये कि उसका ट्रक क्यों पकड़ा, उस का ट्रांजिस्टर क्यों पकड़ा, उसकी घड़ी क्यों पकड़ी । इस तरह का अत्याचार जिसमें कि 19 वर्षीय जवान को जान से मार दिया गया हो, वह इस सदन और देश को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए मैं समझता हूं कि यह बहुत गंभीर मामला है। अभी मुझे सूचना मिली है कि कम से कम 500 लोग ज्ञानी जैल सिंह के घर के सामने बैठे है और उन्होंने खुद लाश को देखा है । उन्होंने उनको क्या आश्वासन दिया इसका मुझे पता नहीं लेकिन मैं चाहूंगा कि सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही करे और पुलिस को इतनी छूट न दी जाय कि किसी ड्राइवर को उतार कर बिना किसी मुकदमें के, बिना किसी चार्ज के लाठियों से मार दिया जाय । एक 19 वर्षीय नौजवान को इस तरह से मार दिया गया है। इस तरह की घटना दिल्ली के आदमी के साथ हुई है। इसलिये केन्द्रीय सरकार से मेरा निवेदन है कि वह इस संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करे ।

श्री सदाशिव बागाईतकर (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदय, यह पोस्ट मार्टम की बात तो मान ली जानी चाहिए ।

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल (मध्य प्रदेश) : पोस्ट मार्टम जरूर हो इसको सरकार को मंजूर कर लेना चाहिए । संसदीय कार्य मंत्री यहां पर है वे इसको स्वीकार तो कम से कम कर लें ।

—

REFERENCE TO THE REPORTED SYSTEMATIC EFFORT TO DAMAGE NEURO-SYSTEM OF THE NAXALITES UNDERGOING IMPRISONMENT IN TAMIL NADU JAILS

श्री सदाशिव बागाईतकर (महाराष्ट्र): मैं आपके माध्यम से सदन का, सरकार का ध्यान, श्री सीताराम केसरी जी का ध्यान खींचना चाहूंगा । जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं वह बहुत ही दर्दनाक बात है । आखिरकार राजनीतिक कैदी हम सब लोग किसी न किसी जमाने में रह चुके हैं और आगे भी रहेंगे । तमिलनाडु के बारे में स्टेट्समैन अखबार में जो रिपोर्ट आई है उसमें जो हकीकत दी गई है उसको पढ़ कर किसी भी मानवीय मन को भयानक दुख होगा । इसमें मान्यवर, यह कहा गया है :

> "Over the past 12 years, a system of beating, torture and solitary confinement has been developed in Tamil Nadu jails to destroy the neuro-system of Naxalites undergoing life imprisonment. The idea *is to incapacitate them mentally* and physically so that, if they stay alive at all after release, political activity will be out of question".

तो मैं चाहूंगा कि इस तरह का अमानवीय व्यवहार जो सजायाफ्ता लोग हैं उनके साथ अगर होता रहे तो क्योंकि वह अपनी रक्षा करने की स्थिति में नहीं होते हैं इसलिए इसका उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर भी आता है। मैं चाहूंगा कि इस चीज को नजर-अंदाज न किया जाए । इसलिए आपका ध्यान और भी खींचना चाहूंगा कि अगर हिंसा से भरे हुए मन को जगह-जगह पर सरकार अपने अफसरों को नहीं रोकेगी तो मानवता नाम की कोई चीज देश में नहीं बच सकती । स्टेट्समैन का जो 27 फरवरी का अंक है उसमें जो वर्णन दिया हुआ है वह यह है । एक कुटुम्ब के सात लोग हैं जो इस वक्त जेल में हैं। आजीवन कारावास की सजा वे भुगत रहे हैं । उनमें एक महिला भी है । उन्हीं सब की जो हकीकत है उससे यह साफ होता है कि उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है । कुछ दिन पहले इस्माइल कमीशन कर के तमिलनाडू में जेलों में सुधार के लिए बैठा था । उसने एक सुझाव दिया था कि नागरिकों की एक समिति बनाई जाए जिसको यह अधिकार हो कि वह जेलों में जा कर देखे कि कैदियों की स्थिति क्या है । लेकिन वे सारी सिफारिशें तमिलनाडू सरकार ने नामंजूर कर दी है । यहां ऐसा होता है कि

[श्री सदाशिव बागाईतकर]

इन कैदियों की स्थिति का पता न तो उनके रिश्तेदारों को लग सकता है, न अखबारनवीसों को लग सकता है और न ही वहां पर पहुंचा जा सकता है, यहां तक कि बर्टी कमेटी यूनियन चलाने वाले भी वहां जा कर जांच नहीं कर सकते। यह स्थिति वहां पर है इसलिए मैं चाहूंगा ...(*Interruptions*)

SHRI R. MOHANARANGAM (Tamil Nadu): Sir, I may be permitted...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him complete.

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: I am reading from the *Statesman*. I would request friends not to take any parochial attitude on this. This has nothing to do with Tamil Nadu Government. The whole police administration in the country is rotten to the core and it is adopting means and methods which are unprintable in any civilised society. We have to look at it from this angle. इसलिए उपसभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि कि सरकार सीताराम केसरी जी से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस सदन के सदस्यों की एक समिति नियुक्त करें जिसको सभी जेलों की स्थिति देखने का अधिकार हो। कुछ दिन पहले इसी सदन में बिहार की जेलों का सारा कांड आया उस विषय में भी आपने एक समिति नियुक्त की थी। जो वहां पर रिफार्म्स करने के लिए समिति आपने नियुक्त की थी उसने अपना काम शुरु किया है या नहीं, अगर किया है तो मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द अपनी सिफारिशें वह सरकार के पास भेजे ताकि जेल के कानूनों में जहां सुधार आवश्यक हों उनको सरकार जल्द अमल में लाए तथा सरकार इसके लिए आवश्यक उपाय करे।

REFERENCE TO THE REPORTED INTER-STATE SPIRIT SCANDAL

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I draw the attention of the Government through you to an important and serious problem which is exising in Tamil Nadu.

The nefarious and notorious spirit scandal is the biggest political corruption and fraud that Tamil Nadu ever faced, in which the Chief Minister and his kith and kin are directly involved. Even according to the Chief Minister of Kerala, from 1978 the scandal has started...

SHRI R. MOHANARANGAM (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, I hope you will give me some time to speak on it.

SHRI V. GOPALSAMY: I have got a clear permission from the Chairman. (*Interruptions*) The Chair should protect me.

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAIDU (Andhra Pradesh): Let us hear what he has to say.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him complete.

SHRI V. GOPALSAMY: Even according to the Chief Minister of Kerala, from 1978 onwards the scandal has started. About 9.96 lakh litres quantity of rectified spirit was allowed by the Tamil Nadu Government to get transported illegally on the basis of forged documents to Kerala. Sir, I quote the *Hindustan Times* dated 11-2-1981:—

> "The kickbacks are estimated to vary between Rs. 12 crore and Rs. 35 crore."

One Kerala contractor, Ahmedkhan, has admitted that he had to give enormous sums of money to get sanction for this illicit trade to the high-ups of Tamil Nadu. Mr. M. G. Chakrapani, brother of Mr. M. G. Ramachandran, Chief Minister of Tamil Nadu, and one actor, Mr. S .S. Rajendran, are directly involved in this fraud and got clearance for this illicit trade. This has been clearly stated in a leading Malayalam daily, *Malayala Manorama*.

The Tamil Nadu Government imposed a ban on the export of spirit in the month of July and then, without any reason, lifted the ban in